



RE

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 389] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 1, 1981/अग्रहायण 10, 1903

No. 389] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 1, 1981/AGRAHAYANA 10, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

अम मंत्रालय

प्रविष्टिका

नई दिल्ली, 30 नवम्बर 1981

सं. 625 (ब्र) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि और प्रक्रीय उपचार अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 का और संशोधन करने के लिए नियमिति की जनाती है, अधीतः—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि (यात्र संशोधन) स्कीम, 1981 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 में पैरा, 68 द के पश्चात् नियमिति पैरा अंतर्स्थापित किया जाएगा, अधीतः—

“68. ऐसे सर्वस्वों को, जो विकलांग हैं, अधिकारी की मंजूरी—

(1) किसी ऐसे सदस्य को, जो विकलांग है, विकलांगता के कारण कठिनाइयों की न्यून करने के लिए अपेक्षित किसी उपस्कर का क्य करने के लिए, निधि में उसके लाभ में से अप्रतिवेद्य अधिकार अनुशासन किया जा सकता है।

(2) उपर्या (1) के अधीन किसी अधिकार का तब तक संदाय नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सदस्य यथास्थिति, आयुक्त या उसके द्वारा इस नियमित प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी के समाधानप्रद रूप में, किसी

सक्षम नियकिता व्यवसायी से इस आमय का विवितसीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करता है कि वह विकलांग है।

(3) इस पैरा के अधीन वो गई अधिकार रकम, सदस्य की छह मास की आधारिक मञ्जूरी और महंगाई भत्ते से, या अविवायों के उन पर स्वाज सहित उसके प्रपत्रे द्विसे से या उपस्कर की लागत से, इनमें से जो भी न्यूनतम हो, अधिक नहीं होगी।

(4) इस पैरा के अधीन कोई द्वितीय अधिकार, इस पैरा के अधीन अनुशासन किसी अधिकार के संदाय की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर अनुशासन नहीं किया जाएगा।”

पार दिप्पण: प्रधान स्कीम प्रसिद्धना सं. 620 नं. आ० 1509, तारीख 2 मित्तम्बर, 1952 द्वारा, भारत के राजपत्र, 1952 में प्रकाशित की गई थी।

[सं. एस० 70012/15/81-पी एफ II]

श्री गोविंदराजन, गवरर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 1981

G.S.R. 625(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby

makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Sixth Amendment) Scheme, 1981.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 after paragraph 68M, the following sub-paragraph shall be inserted namely :—

"68N :— Grant of advance to members who are physically handicapped :—

(1) A member, who is physically handicapped, may be allowed a non-refundable advance from his account in the Fund, for purchasing an equipment required to minimise the hardship on account of handicap.

(2) No advance under sub-paragraph (1) shall be paid unless the member produces a medical certificate

from a competent medical practitioner to the satisfaction of the Commissioner or such other officer as may be authorised by him in this behalf to the effect that he is physically handicapped.

(3) The amount advanced under this paragraph shall not exceed the members' basic wages and dearness allowance for six months or his own share of contributions with interest thereon or the cost of the equipment, whichever is the least.

(4) No second advance under this paragraph shall be allowed within a period of three years from the date of payment of an advance allowed under this paragraph."

Foot Note : Principal scheme published vide Notification No. S.R.O. 1509 dated 2nd September, 1952, Gazette of India 1952.

[No. S. 70012/15/81-PF. II]

V. GOVINDRAJAN, Under Secy.